RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 23 नवंबर 2023 वर्ष 05 अंक 211 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

पेंशन एक बुनियादी हक

बकाया राशि के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता - हाईकोर्ट

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने एक शख्स की सेवानिवृत्ति के बाद दो साल से ज्यादा समय तक पेंशन का भुगतान न करने पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि पेंशन एक बुनियादी हक है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसकी राशि के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। यह उनके लिए आजीविका का बड़ा स्रोत है।

न्यायमूर्ति जी.एस.कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि राज्य में इस तरह की स्थिति पूरी तरह से अनुचित है। खंडपीठ जयराम मोरे नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मोरे ने 1983 से मई 2021 तक पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में 'हमाल' (कुली) के रूप में काम किया था। उन्होंने अदालत से सरकार को उनकी पेंशन राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि जयराम मोरे ने अपने कार्यकाल के दौरान बेदाग सेवा दी, बावजूद इसके उन्हें तकनीकी आधार पर पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया। मोरे ने अपनी याचिका में दावा किया कि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विभाग को सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा कराने के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

पीठ ने कहा, कार्यवाही की शुरूआत से ही हम सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति तीस वर्षों की लंबी बेदाग सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो क्या उसे ऐसी दुर्दशा का सामना करना चाहिए और पेंशन के बुनियादी अधिकार से वंचित होना चाहिए, जो उसकी आजीविका का बड़ा स्रोत है।

31 दिसंबर तक सुनवाई पूरी कर देना है फैसला

विधायकों की अयोग्यता मामले में मैराथन सुनवाई शुरू

34 याचिका दायर

शिवसेना विधायकों की तरफ से 34 याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई छह ग्रुप में की जा रही है, जबकि शिंदे गुट लगातार अलग-अलग सुनवाई की मांग कर रहा है। उद्धव व शिंदे गुट की पूरी बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी याचिकाओं को 6 समूह में बांटकर सुनवाई करने का फैसला लिया।

मुंबई : एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे सेना के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका की सुनवाई मंगलवार से फिर शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने साफ किया है कि सुनवाई नियम कानून के तहत ही किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अयोग्यता मामले की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के सामने मंगलवार की सुबह सुनवाई शुरू हुई।

जिरह के दौरान शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने उद्धव गुट के विधायक व मुख्य सचेतक सुनील प्रभु से कई सारे सवाल पूछे, जिसका प्रभु ने उत्तर दिया। ज्यादातर समय इनके बीच जिरह में ही निकल गया। अब बुधवार की सुबह 11 बजे फिर से जिरह होगी। बुधवार 22 नवंबर से 24 नवंबर और तीन दिनों के अवकाश के बाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि जरूरत पड़ी, तो नागपुर में शीतकालीन सत्र के दौरान भी सुनवाई करेंगे। मंगलवार को सुनवाई की नई समय सारिणी सामने आई है।

फिर बढ़ सकते हैं प्याज के दाम, फल और दाल भी करेंगी हलाकान

मुंबई : आने वाले समय में किचन का बजट बिगाड़ सकता है क्योंकि जिस राज्य में प्याज, दाल, चीनी, फल और सब्जियां अधिक मात्रा में उगाई जाती है वहां सुखे जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश न होने की वजह से ये सभी उत्पाद खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में रबी की फसल बोए जाने के बाद से बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से किसानों के फसल बरबाद हो रहे हैं। महाराष्ट्र प्याज, दाल, चीनी, फल और सब्जियों का प्रमुख उत्पादन वाले राज्यों में से एक है। यहां बीते वर्ष की तुलना में प्रदेश में 20 फीसदी कम बारिश हुई है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पानी की कमी की वजह से रबी सीजन की प्याज की बुआई कम होने की संभावना है।

मनोज जरांगे ने दी चेतावनी

24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण नहीं मिला तो आंदोलन रोका नहीं जा सकेगा

ठाणे: मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटील ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते कहा कि अगर 24 दिसंबर तक आरक्षण नहीं दिया गया, तो उसके बाद होने वाले आंदोलन को सरकार नहीं रोक पाएगी।

इस दौरान, पाटील ने छगन भुजबल सहित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार पर भी निशाना साधा। पाटील ने कहा, 'राज्य में मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच दंगे न हों, इसके लिए हम दिन-रात बैठकें कर रहे हैं। पुलिस हम पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ, भुजबल दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भुजबल का समर्थन कर रहे हैं? क्या सरकार दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है?' उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार उनके खिलाफ चाहे जितने भी मुकदमे दर्ज कर ले, हम न डरेंगे, न रुकेंगे। मराठों के कल्याण के लिए कोई भी अपराध करने तैयार हूं।'

ठाणे आए पाटील का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान दुपहिया रैली निकाली गई और पाटील पर फूलों की वर्षा की गई। सभा के दौरान, पाटील के लिए बड़ी कुर्सी मंगाई गई थी, जिसे हटवाकर वह प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठे। पाटील ने कहा, 'भुजबल कहते हैं कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, मराठा आरक्षण का अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने अभ्यास किया या नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ आरक्षण लिया है। मेरे पास पढ़ने-पढ़ाने का समय नहीं है।' पाटील ने सुझाव दिया कि भुजबल को जेल जाने के बाद फिल्म की कहानी लिखनी चाहिए। पाटिल ने साफ किया कि 25 दिसंबर को वह आगे की भूमिका स्पष्ट करेंगे।

मनोज जरांगे ने कहा कि मराठों को ओबीसी वर्ग से आरक्षण न मिले, इसके लिए भुजबल राज्यभर में जितना कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उतना ही मराठों का लाभ होगा। मराठा समाज के जो कुछ लोग एक नहीं हुए थे, भुजबल के कार्यक्रमों की वजह से वे भी एक हो गए हैं।

पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया

सरकारी कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

मुंबई : महाराष्ट्र में फिर से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन ने इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाए जाने पर बेमियादी हड़ताल करने की चेतावनी दी है। पुरानी पेंशन को लेकर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है। पुरानी पेंशन समिति ने 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट राज्य के वित्तमंत्री अजित पवार को सौंप दी है। यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू करने से जुड़ी एक रिपोर्ट 21 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार को सौंपी गई है। बख्शी कमेटी की रिपोर्ट डिप्टी सीएम व वित्तमंत्री अजित पवार को दी गई। पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकार ने पूर्व चार्टर्ड अधिकारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव, केपी बख्शी थे। सरकार द्वारा इस अध्ययन समिति का गठन 14 मार्च 2023 को किया गया था. लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी का समय दो बार बढ़ाया भी गया।

संपादकीय / लेख

युवा वोटर मांगे नौकरी

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी है, वहां युवा नौकरियों और रोजगार का मुद्दा खूब गूंज रहा है। सिर्फ इसी आधार पर राजनीतिक दलों को कितना जनादेश प्राप्त होगा, यह कहना अनिश्चित है, लेकिन दलों के घोषणा-पत्रों में सरकारी नौकरियों को लेकर आश्वासन प्रमुख रूप से बांटे गए हैं। भाजपा या कांग्रेस के अलावा, मिजोरम की क्षेत्रीय पार्टियों को भी वायदा करना पड़ा है कि उनकी सरकार युवाओं के लिए इतनी सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। रोजगार के क्षेत्र में बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं कि किस सरकार के दौरान कितने पेपर लीक कराए गए। अव्वल तो सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षाएं लटकाई जाती रही हैं। यदि परीक्षा हो गई, तो उनके नतीजे अनिश्चित अंधेरों में डूब जाते हैं। यदि परीक्षाओं के बाद सफल चेहरों को नियुक्ति-पत्र मिल भी गए, तो ज्वाइनिंग में आनाकानी की जाती रही है। अंततः अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं और वहां भी सब कुछ अनिश्चित है। इन धांधलियों और घपलों पर युवा मतदाता सरकारी नौकरियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त कैसे हो सकता है? घोषित राजनीतिक आश्वासनों पर जनादेश दिए जाएंगे, सरकारें बनेंगी, उसके बाद नौकरी या रोजगार का वायदा, समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से, पूरा नहीं किया गया, तो युवा वोटर क्या कर सकते हैं? जनादेश तो पांच साल के लिए होता है। पांच साल के बाद राजनीतिक परिदृश्य और समीकरण क्या होंगे, पार्टियां इन चिंताओं में दुबली नहीं हुआ करतीं। अलबत्ता युवाओं के सामने आंदोलन का रास्ता जरूर खुला है।

उनसे पूर्ण न्याय कब मिला है? बहरहाल तेलंगाना में कांग्रेस ने ह्यजॉब कलैंडरह्न तय करने का वायदा किया है। भाजपा ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के मद्देनजर पारदर्शी और समयबद्ध समाधान देने का वायदा किया है। दोनों दलों को तेलंगाना में जनादेश मिलने के आसार नहीं हैं। राजस्थान में उन युवाओं को समर्थन दिया जा रहा है, जिन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती की निरंतर और सिलसिलेवार देरी के खिलाफ आवाज उठाई है। तेलंगाना और राजस्थान में युवा बेरोजगारी दर क्रमशः 15.1 फीसदी और 12.5 फीसदी है, जो देश भर में सर्वाधिक हैं। कमोबेश बेरोजगारी की राष्ट्रीय दर करीब 8 फीसदी से तो ज्यादा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं विवादों और घोटालों में संलिप्त रही हैं। लगातार पेपर लीक, परीक्षा परिणामों में धांधलियों, कानूनी पचड़ों के कारण बीते चार साल में 8 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। मध्यप्रदेश में आज भी ह्यव्यापम घोटालेह्न की गूंज सुनाई देती है। हालांकि अब यह उतना प्रासंगिक चुनावी मुद्दा भी नहीं है। पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के मुताबिक, मप्र में युवा बेरोजगारी की दर चुनावी राज्यों में सबसे कम 4.4 फीसदी है। तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम (11.9 फीसदी) में युवा बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। छत्तीसगढ़ में यह दर 7.1 फीसदी है। बेशक सरकारी नौकरियों और रोजगार के बेहतर अवसरों के आश्वासन सभी राजनीतिक दलों ने बांटे हैं, लेकिन युवा मतदाताओं की चिंताओं, प्रतिबद्धताओं और उनके सरोकारों पर ह्याराजनीतिह्न ज्यादा की जा रही है। महिलाओं में बेरोजगारी की दर अधिक और गंभीर है। बहरहाल ये आंकड़े और संकेत चिंताजनक हैं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना

मुंबई : केंद्र की भाजपा सरकार देश की अच्छी अर्थव्यवस्था के ढोल पीट रही है। विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। मगर यह सब छलावा साबित हो रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी के बीच एक अमेरिकी फर्म ने अगले साल के जीडीपी ग्रोथ पर बड़ा बयान दिया है। इसके अनुसार, हिंदुस्थान की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) २०२४ में जमीं पर होगा यानी इसमें गिरावट आएगी।

जानकारों का मानना है कि अगले साल यह गिरावट के साथ ६.३ प्रतिशत से नीचे जा सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, अगला वैष्ठलेंडर साल दो हिस्सों का होगा, जिसमें आगामी आम चुनाव से पहले सरकारी खर्च वृद्धि इसका मुख्य कारण होगा, जबकि चुनाव के बाद निजी क्षेत्र में फिर से तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, वित्त वर्ष के संदर्भ में वित्त वर्ष २०२४-२५ में वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष में अनुमानित ६.२ प्रतिशत में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। एक बयान में गोल्डमैन सैक्स ने कहा, 'इस क्षेत्र में हिंदुस्थान में संरचनात्मक वृद्धि की सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। हमारा मानना है कि २०२४ में जीडीपी वृद्धि दर ६.३ प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है।'कंपनी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि देश वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों, डॉलर की लगातार मजबूती और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसे संभावित बाहरी झटकों के प्रति कम 'संवेदनशील' है। ब्रोकरेज ने कहा कि वृद्धि परिदृश्य को लेकर जोखिम समान रूप से संतुलित है, लेकिन 'मुख्य घरेलू जोखिम राजनीतिक अनिश्चितता से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि २०२४ की अप्रैल-जून तिमाही में आम चुनाव होने वाले हैं।' पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ चुनावी मौसम पहले से ही चल रहा है। इसके बाद आम चुनाव का मौसम शुरू होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चुनावों के नतीजों पर निवेशकों द्वारा आर्थिक सुधारों और / या नीति निरंतरता के दृष्टिकोण से 'गहराई से नजर' रखी जाएगी। फर्म ने संभावना जताई है कि प्रमुख उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति २०२४ में ५.१ प्रतिशत रहेगी। हालांकि, रिजर्व बैंक का अनुमान है कि मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत रहेगी।

बेटे को स्कूटी पर बैठने से मना किया तो पिता ने नाबालिग को मारी गोली...

पुलिस ने आरोपित को दबोचा

दिल्ली : करावल नगर इलाके में स्कूटी पर बैठने से मना करना 14 वर्षीय नाबालिग को भारी पड़ गया। इससे नाराज होकर स्कूटी पर बैठने वाले 16 वर्षीय नाबालिग अपने पिता को बुला लिया। पिता ने बेटे के साथ मिलकर नाबालिग की जांघ में गोली मार दी। गंभीर हालत में नाबालिग को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता पीड़ित

वारदात के कुछ देर बाद पुलिस ने शख्स व उसके नाबालिग बेटे को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपित की पहचान नीरज के रूप में हुई है। आरोपितों के पास से एक पिस्टल बरामद की है। नीरज के बड़े बेटे मयंक व उसके दोस्त शिवम की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित अपने परिवार के साथ करावल नगर स्थित देवी नगर में रहता है। परिवार में माता-पिता और एक छोटा भाई है। पीड़ित घर के पास के सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। मंगलवार रात सवा आठ बजे पीड़ित 23 फुटा रोड, शिव विहार में अपने चाचा की दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान के बाहर उसके पिता की स्कूटी खड़ी हुई थी।

नाराज पिता ने नाबालिग को मारी गोली

आरोप है उसी दौरान एक नाबालिग आया और स्कूटी पर बैठ गया। पीड़ित ने उसे स्कूटी पर बैठने से मना किया। वह पीड़ित के साथ गाली गलौज करने लगा। बाद में देख लेने की धमकी देकर आरोपित वहां से चला गया। कुछ देर के बाद वह अपने पिता, बड़े भाई और अन्य के साथ वहां पहुंचा। आरोपित नाबालिग के पिता नीरज ने पीड़ित को गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। कुछ देर के बाद पुलिस ने देव नगर से ही पिता-पुत्र को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ कर पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह पिस्टल कहां से खरीदकर लाया था।

प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा...

बढ़ रहे खांसी के मरीज

मुंबई : मुंबई और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ता वायु प्रदूषण आम लोगों के लिए धीरे-धीरे दम घोंटू बनता जा रहा है। आलम यह है कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। इस समय मुंबई में खांसी के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर घाती सरकार और मनपा प्रशासन ने दावा किया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम संभावित उपायों को किया जा रहा है। हालांकि, जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं।

प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है और सभी उपाय धरे के धरे रह जा रहे हैं। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक, बीकेसी में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़कर १९६ एक्यूआई पर पहुंच गया है। मानसून की विदाई के बाद से रिकॉर्ड प्रदूषण स्तर के कारण सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा दुर्लभ हो गई है। इससे न केवल प्रतिष्ठान और आम नागरिक, बल्कि चिकित्सक भी चिंतित हैं। उन्होंने सलाह दी है कि इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल और एलर्जी से दूर रहना ही एकमात्र उपाय है।

उल्लेखनीय है कि मुंबई पिछले कुछ महीनों से बढ़ते वायु प्रदूषण की चपेट में है। हालांकि, मनपा दावा कर रही है कि वह पूरे शहर में वायु प्रदूषण को रोकने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय कर रही है। इन सबके बीच पिछले कुछ दिनों की ही तरह मुंबई में मंगलवार की सुबह भी धुंध भरी रही। साथ ही तापमान २३ से ३४ डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इन सबके बीच सोमवार को जहां वायु प्रदूषण में सुधार हुआ और मुंबई में औसत एक्यूआई १०४ पर पहुंच गया था, वहीं वह कल फिर से बढ़कर १३१ पर पहुंच गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, मुंबई के भांडुप में १२२, कोलाबा में १३०, मालाड में १४८, मझगांव में १४४, वर्ली में ९३, बोरीवली में १४५, बीकेसी में १९६, चेंबूर में १२७, अंधेरी में ११६ और नई मुंबई में १६९ एक्यूआई दर्ज किया गया।

जेजे अस्पताल के प्रोफेसर डॉ. मधुकर गायकवाड़ के मुताबिक, खांसी की अवधि जो पहले एक सप्ताह में ठीक हो जाती थी, अब उसे ठीक होने में पंद्रह दिन से एक महीने तक का समय लग रहा है।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 23 नवंबर 2023

नियमों की उड़ रही सरेआम धज्जियां... बिना कत्लखाने के चल रहा है अवैध मांस बिक्री का व्यवसाय

उल्हासनगर : उल्हासनगर में एक भी वैध कत्लखाना नहीं है। इतना ही नहीं उल्हासनगर में पशु चिकित्सक तक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सैकड़ों बकरे काटे जाते हैं। पशु चिकित्सक के अभाव में सैकड़ों जानवर, जो बीमार हैं, उन्हें सस्ती दरों पर खरीदकर काटे जाने की चर्चा आम लोगों के बीच हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर उल्हासनगर का स्वास्थ्य विभाग जानवरों के स्वास्थ्य परिक्षण के बिना उन्हें काटने की इजाजत वैष्ठसे दे रहा है? उल्हासनगर में मांस विक्रेता खुले आम जानवरों का कत्ल कर उनका मांस बेच रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जानवरों को काटने के बाद उसके खून, अन्य अवशेष का क्या किया जाता है? अन्य मनपा में कत्लखाने में काटे गए जानवरों के खून व अन्य अवशेष को बंद वाहन से ले जाया जाता है। परंतु उल्हासनगर में ऐसी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है।

उल्हासनगर में जब नगरपालिका थी उस समय अलग जगह पर कत्ल खाने का बाजार हुआ करता था। लेकिन आज बिना किसी डर के किसी भी जगह पर मांस बेचा जा रहा है। मांस को कपड़े से ढंककर रखने के नियम हैं। जबकि उल्हासनगर में खुले में मांस बिक्री शुरू है। खुले में लटकाई गई मांस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। उल्हासनगर में किसी भी मांस विक्रेता पर नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाही शायद ही की गई हो? उल्हासनगर में दो नंबर ओटी, आजाद नगर, शहद फाटक जैसी तमाम जगहों पर मांस बेचने के नियमों की धज्जियां उड़तीं देखी जा सकती हैं।उल्हासनगर को मनपा का दर्जा मिले २६ वर्ष होने के बाद भी महानगर पालिका अधिनियम अभी तक लागू नहीं हो सका है, जिसकी मिसाल है उल्हासनगर मनपा। परिसर में मांस बिक्री का व्यवसाय बिना किसी रोक-टोक के बिंदास चल रहा है। उल्हासनगर मनपा में अज्ञानी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की बागडोर देने के कारण अधिकारियों की अनदेखी का ही नतीजा है कि यहां मांस बिक्री का व्यवसाय चल रहा है। इसके चलते शहर में बदबू की भरमार अर्थात वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। मांस बेचनेवाले नियमों को ताक पर रखकर मांस बिक्री कर रहे हैं। मांस बिक्री व्यवसाय के चलते शहर में किस तरह से नियमों की अवहेलना हो रही है, इसका खुलासा दोपहर का सामना के सिटीजन रिपोर्टर राजेश पवार ने किया है।

बता दें कि उल्हासनगर में एक भी वैध कत्लखाना नहीं है। इतना ही नहीं उल्हासनगर में पशु चिकित्सक तक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सैकड़ों बकरे काटे जाते हैं। पशु चिकित्सक के अभाव में सैकड़ों जानवर, जो बीमार हैं, उन्हें सस्ती दरों पर खरीदकर काटे जाने की चर्चा आम लोगों के बीच हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर उल्हासनगर का स्वास्थ्य विभाग जानवरों के स्वास्थ्य परिक्षण के बिना उन्हें काटने की इजाजत वैष्ठसे दे रहा है? उल्हासनगर में मांस विक्रेता खुले आम जानवरों का कत्ल कर उनका मांस बेच रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जानवरों को काटने के बाद उसके खून, अन्य अवशेष का क्या किया जाता है?

गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में फेंका कचरा...

आनंद महिंद्रा ने उठाए सवाल तो बीएमसी ने आरोपी पर लगाया 10,000 जुमार्ना

मुंबई : बीएमसी ने गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में कचरा फेंकने वाले की पहचान कर उस पर 10000 रुपये जुमार्ना लगाया है। मुंबई में कचरा फेंकने पर यह बीएमसी द्वारा लगाया गया सबसे अधिक जुमार्ना है। दंड लगाने की कार्रवाई ए वॉर्ड ने की है।जिस व्यक्ति पर जुमार्ना लगाया गया, उसका नाम हाजी अब्दुल रहमान शाह कादरी है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक

विडियो में एक व्यक्ति टैक्सी से उतर कर गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में फूलों का कचरा फेंक रहा था। बीएमसी ने मुंबई पुलिस की मदद से विडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कचरे के साथ उक्त व्यक्ति को लाने वाली टैक्सी का नंबर ट्रेस कर उस व्यक्ति की पहचान की गई। 58 सेकंड के इस विडियो में देखा गया कि कुछ लोग टैक्सी में भरकर कचरा लाते हैं। फिर समुद्र के किनारे गाड़ी लगाकर, फटाफट बैग में भरे सूखे फूल और पूजा के बाद बचे हुए अन्य सामान को समुद्र में डालकर वहां से चल पड़ते हैं। एक व्यक्ति ने इसका विडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो वायरल हो गया।

आनंद महिंद्रा की पोस्ट के बाद जागी बीएमसी

आनंद महिंद्रा की पोस्ट के बाद बीएमसी ऐक्शन में आई और पुलिस की मदद से कचरा फेंकने वाले को ढूंढना शुरू कर दिया। टैक्सी की गाड़ी नंबर से बीएमसी उस व्यक्ति तक पहुंची और उस पर जुमार्ना लगाया गया।

मुंबई में हो सकती है बेमौसम बरसात !

24 से 26 नवंबर के बीच पानी में धुल सकता है वायु प्रदूषण

मुंबई : महानगर में एक बार फिर बेमौसम बरसात हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश 24 से 26 नवंबर के बीच मुंबई महानगर के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, बारिश से मुंबईकरों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इससे शहर की एयर क्वॉलिटी में सुधार की उम्मीद है। मुंबई का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इससे पहले 8 और 9 नवंबर को भी यहां बेमौसम बरसात हुई थी। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उपनगर का अधिकतम पारा 35.6 डिग्री सेल्सियस और शहर का 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शहर का न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और उपनगर का 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तीन दिन पहले उपनगर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का था, लेकिन मंगलवार को इसमें बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 24 नवंबर से मुंबई के आसमान में बादलों का जमावड़ा हो सकता है, फिर 25 की दोपहर या शाम तक गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 26 को भी बारिश होने का अनुमान है।

..तो नहीं करानी पड़ेगी कृत्रिम बारिश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में धूल और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बारिश की बात कही थी। शिंदे ने बताया कि स्थानीय निकाय ने पहले ही दुबई स्थित एक कंपनी से संपर्क किया है। इस कंपनी के पास कृत्रिम बारिश कराने का अच्छा अनुभव है और इसके साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि मुंबई में अगर दो दिनों तक बारिश होगी तो वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी।

जालना लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को करें बर्खास्त, मराठा आरक्षणकर्ता मनोज जरांगे ने की मांग

मुंबई : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को कहा कि जालना जिले में सितंबर में समुदाय के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को जब तक सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक मराठा चुप नहीं बैठेंगे। नासिक जिले के इगतपुरी में मराठा समुदाय की एक रैली को संबोधित करते हुए जरांगे ने मांग की कि उन लोगों के नामों का खुलासा किया जाए, जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था।

जरांगे ने एक सितंबर की घटना का जिक्र करते हुए दावा किया, ''हम जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में (मराठा आरक्षण के लिए) शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हम पर हमला किया और लाठियों से पीटा। बाद में, हमारे (मराठा प्रदर्शनकारियों) खिलाफ साजिश रचने और हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, ''जब तक लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता, हमारे गांव या पूरे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शांति नहीं मिलेगी।

पुलिस ने एक सितंबर को अंतरवाली सरती गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। यह कार्रवाई तब की गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को जरांगे को अस्पताल में स्थानांतरित करने से कथित तौर पर रोकने का प्रयास किया था। जरांगे मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 23 नवंबर 2023

मानहानि मामले में भाजपा MLA नीतेश राणे के खिलाफ 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा दी गयी मानहानि की शिकायत के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नीतेश राणे को मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया। मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि नीतेश राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने पिछले महीने नीतेश राणे को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने मंगलवार को कहा कि नीतेश राणे अनुपस्थित रहे और उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ। राउत के वकील ने तब एक आवेदन दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की।

नीतेश राणे को अब उस तारीख पर हाजिर होना होगा और वारंट रद्द कराना होगा। इस साल मई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने कथित रूप से राउत को 'सांपबताया था और कहा था कि वह उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और राकांपा में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दी तथा कथित मानहानिकारक एवं सरासर झूठीटिप्पणी करने को लेकर नीतेश राणे के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया।

बेस्ट बेड़े में 3337 बस रखने मनपा उपलब्ध कराएगी निधि - मनपा आयुक्त

मुंबई : बेस्ट बेड़े में घटी बसों की संख्या को दोबारा 3337 बस बेस्ट उपक्रम में लाने के लिए मनपा बेस्ट को जल्द निधि उपलब्ध कराएगी इस तरह का आश्वसन मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मंगलवार को बेस्ट पूर्व अध्यक्षो के साथ हुई बैठक में कही। मंगलवार को बेस्ट के पूर्व अध्यक्षो आशीष चेंबूरकर, अनिल पाटनकर और अनिल कोकील के एक प्रतिनिधिमंडल ने मनपाआयुक्त इकबाल सिंह चहल से मुलाकात की और मांग की कि बेस्ट बेड़े में बेस्ट की खुद की 3337 बसों की संख्या बनी रहे इसके लिए तत्काल उपाय किए जाने की मांग की। इस समय बेस्ट के पास खुद की मात्र 1686 बस ही शेष रह गई है जबकि मनपा आयुक्त ने बजट में ऐसा आश्वासन दिया था कि बेस्ट बेड़े में 3337 बस संख्या से कम नहीं होने दिया जायेगा। जून 2019 में मनपा के तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी ने बेस्ट कामगारों के साथ हुए समझौते के अनुसार बेस्ट की खुद की बस की संख्या हर समय 3337 से कम नहीं होगी ऐसा लिखित अनुबंध किया है। लेकिन इस समय मात्र 1686 बस ही बेस्ट स्व-स्वामित्व वाली शेष है। बाकी की बस भाड़े पर ली गई बस है। बसों की संख्या घटने से यात्रियों का बुरा हाल हो रहा है घंटो यात्रियों को बस स्टॉप पर खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है। इस बैठक में मनपा आयुक्त चहल ने बसों की संख्या बढ़ाने के लिए जल्द फंड उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। आयुक्त ने बसों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से भी इसकी पूर्तता करने के लिए चर्चा करने की जानकारी दी। मनपा आयुक्त ने बेस्ट को बस खरीदने के लिए लगने वाले फंड की मान्यता देने की बात कही। आयुक्त ने कहा की बेस्ट के स्वामित्व वाले बेड़े में बसों की संख्या 3337 करने के लिए धनराशि पूरी की जाएगी और जल्द से जल्द बेस्ट की अपनी बसें खरीदने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

2025 के बाद बेस्ट की खुद की नहीं होगी एक भी बस...

बेस्ट प्रशासन को बस खरीदने के लिए मनपा प्रशासन ने पैसा नहीं दिया तो जसि तरह बसों की संख्या घट रही है और हर साल बस स्क्रैप एम-जा रही है 2025 तक बेस्ट के बेड़े ने खुद की एक भी बस शेष नहीं रहेगी। शिवसेना नेता विधायक आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है और राज्य सरकार और मुंबई मनपा को स्व-स्वामित्व वाली बसें खरीदने के लिए तत्काल आदेश जारी करने की मांग रखी है। पिछले अनुबंध एक अनुसार मनपा बेस्ट को 100 करोड़ रुपए देगा लेकिन मनपा की ओर से अभी तक उसकी पूर्तता नहीं हुई जिस पर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि समझौते के अनुसार इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।

नागरिकों के सामने पानी की गंभीर समस्या

मुंबई : कुर्ला के एल वॉर्ड के अंतर्गत साकीनाका के हिल क्रमांक-तीन में बरसों से कम दबाव से पानी आने से जनता त्रस्त है। बता दें कि हिल क्रमांक-३ एक ऐसा इलाका है, जो पहाड़ी पर बसा हुआ है। हिल क्रमांक-३ के परिसर में संजय नगर, अशोक नगर, संतोषी माता नगर तथा हिमालय सोसायटी का एक बड़ा हिस्सा आता है। यह सभी इलाके पहाड़ी पर बसे हुए हैं। १ वर्ष पूर्व तक इस इलाके में पानी की नियमित सप्लाई होती थी। पिछले एक वर्ष से पानी बहुत कम दबाव से आ रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ के अधिकांश लोगों के घरों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा यह होता है कि लोग ऊपर से नीचे उतरकर निचले हिस्सों से पानी भरकर उन्हें गैलन में उठाकर पहाड़ पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। इस संदर्भ में कुर्ला के यह एल वॉर्ड में पानी विभाग से कई बार शिकायत की गई।

अजित गुट के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो

चुनाव आयोग सुनवाई में शरद पवार गुट की मांग

मुंबईः एनसीपी में फूट के बाद पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह पर कब्जे को लेकर सोमवार को केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई हुई। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार द्वारा शुरू की गई पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकते हुए चुनाव आयोग में याचिका दायर की है। शरद पवार गुट की ओर से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखते हुए दावा किया अजित पवार गुट ने कार्यकताओं के साथ-साथ पार्टी पदाधिकारियों के भी फर्जी शपथ पत्र जमा करवाए हैं। शरद पवार गुट ने आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है अभिषेक मनु सिंघवी, शरद पवार गुट के वकील ने कहा, अजित पवार गुट ने पदाधिकारियों का जो हलफनामा दिया, उसमें कई फर्जी हैं। यह एक शर्मनाक काम है। हमने मांग की है कि इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मामला दायर किया जाना चाहिए।

समय बर्बाद करने का आरोप

दूसरी ओर अजित पवार गुट की तरफ से अधिवक्ता नीरज किशन कौल और मनिंदर सिंह ने बहस करते हुए कहा कि शरद पवार गुट पर लगातार एक ही तरह के मुद्दे उठाने और समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। सोमवार की बहस खत्म होने बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 24 नवंबर को होगी।

अजित की तरफ से उनके बेटे पार्थ रहे मौजूद

चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान एक ओर जहां पार्टी अध्यक्ष शरद पवार अपनी बेटी व सांसद सुप्रिया सुले और पूर्व मंत्री जितेंद्र अहवाड के साथ मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से उनके बड़े बेटे पार्थ पवार मौजूद थे। पार्टी की इस लड़ाई में दादा-पोता आमने-सामने दिखाई दिए।

आयोग ने शरद पवार गुट की खिंचाई की

केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि शरद पवार हलफनामे के उन बिंदुओं का दोबारा जिक्र न करें, जिन पर हमने पिछली सुनवाई में बहस की थी। अब इस मामले में आगे की बहस होनी चाहिए। शरद पवार गुट ने अजित पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को भी चुनौती दी है।

मीडिया के सामने पदाधिकारी को किया पेश

सिंघवी ने मीडिया के सामने एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर प्रताप सिंह को पेश करते हुए कहा कि सिंह शरद पवार गुट के साथ हैं। उन्होंने ऐसा शपथ पत्र भी दिया है। लेकिन अजित गुट ने प्रताप सिंह का फर्जी हलफनामा बना कर चुनाव आयोग में जमा कराया है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके चुनाव आयोग को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजित गुट के दावे चुनाव आयोग में टिकने वाले नहीं हैं।

विश्व कप की हार पर भड़के नाना! पनौती शब्द बीजेपी से इतना क्यों जुड़ा है?- नाना पटोले

मुंबई : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल उठाया है कि पनौती शब्द बीजेपी से इतना क्यों जुड़ा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पनौती शब्द से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ है तो नाना पटोले ने बीजेपी को आत्ममंथन करने की सलाह दी है. नाना पटोले ने कहा कि जब राहुल गांधी राजस्थान में भाषण दे रहे थे तो कुछ युवाओं ने आवाज उठाई. उनका इशारा पनौती शब्द की तरफ था जो क्रिकेट मैच के आधार पर प्रचलित हुआ था. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पनौती के कारण हार गई। लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया. पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि बीजेपी से पनौती शब्द इतना क्यों जुड़ा है?

एक्स पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय टीम को जीतना चाहिए. लेकिन खेलों का राजनीतिकरण किया जा रहा है. पटोले ने यह भी कहा कि इससे खिलाड़ी के दिमाग पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ी और देशवासी दुखी हैं। हमने 10 वर्षों में विश्व कप नहीं जीता है। कांग्रेस के समय हम जीत रहे थे। मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं। पटोले ने यह भी कहा, लेकिन खेल में राजनीति आ गयी है, जिसका नतीजा यह है कि हम विश्व कप प्रतियोगिता में लगातार पिछड़ रहे हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com